कठपुतली कॉलोनी के पुनर्वास का प्लान तैयार

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

कठपुतली कॉलोनी के लिए दिल्ली संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को लेटर लिखा है

दिल्ली सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के पुनर्वास के लिए नीति बनाई है और इसी नीति के तहत कठपुतली कॉलोनी जे.जे बस्ती के लिए भी पुनर्वास प्लान बनाया गया है। दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने कठपुतली कॉलोनी के पुनर्वास को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को लेटर लिखा है और कहा है कि डीडीए को भी इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता दिखाना चाहिए। लेटर में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है और बोर्ड ने सभी एजेंसियों के लिए प्रोटोकॉल बनाया है। लेटर में केंद्रीय मंत्री से मांग की गई है कि नोडल एजेंसी के रूप में बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल और तय नीतियों के हिसाब से कठपुतली कॉलोनी के पुनर्वास के संबंध में डीडीए को निर्देश जारी किए जाएं। खेतान ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।

खेतान ने अपने लेटर में कठपुतली कॉलोनी जेजे बस्ती में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में भी बताया है। उन्होंने लिखा है कि डीडीए ने इस बस्ती के इन-सीटू पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और सात साल से ज्यादा वक्त पहले एक प्राइवेट बिल्डर को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक इस बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के मामले में नाममात्र की प्रगति हुई है। प्रोजेक्ट सौंपे जाने के बाद से ये बस्ती पुनर्वास की प्रक्रिया में है लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इसकी वजह से बस्ती में सुधार के काम ठप पड़े हुए हैं। बस्ती के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली अर्बन इंप्रूवमेंट बोर्ड के जरिए एक नीति बनाई है। इस दौरान हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर डूसिब को एक प्रोटोकॉल तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें झुग्गियों और जेजे बस्तियों को हटाने से पहले, हटाने की कार्रवाई के दौरान और हटाने के बाद के कदमों का जिक्र होगा। डूसिब ने प्रोटोकॉल तैयार कर लिया है और दिल्ली पुलिस सहित सभी एजेंसियों को इस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लेटर में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने प्लान तैयार किया है और अब डीडीए को भी निर्देश दिए जाएं ताकि कठपुतली कॉलोनी का पुनर्वास हो सके।